



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 26, 2006/आषाढ़ 5, 1928

No. 102]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 26, 2006/ASADHA 5, 1928

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया

(कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गठित)

कम्पनी सचिव (संशोधन) विनियमावली, 2006

(सन् 2006 की आई. सी. एस. आई. सं. 2)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2006

सं. 710/1(एम)/1.— 2 सितम्बर 2005 को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, अनुभाग 4 में कम्पनी सचिव अधिनियम 1980 (1980 का 56) में आगे संशोधन करने के लिए विनियमावली का प्रारूप प्रकाशित किया गया था, जिसमें जिस तारीख से उक्त राजपत्र की प्रतियां जनसामान्य को प्राप्त होने से 45 दिन के अन्दर प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनसामान्य को 5 सितम्बर, 2005 को उपलब्ध हो गई थी।

और जनसामान्य से कोई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अतः परिषद् ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से कम्पनी सचिव अधिनियम 1980 (1980 का 56) की धारा (3) के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी सचिव विनियामवली, 1982 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों को कम्पनी सचिव (संशोधन) विनियमावली, 2006 कहा जाएगा।
- (ii) ये विनियम भारत के राजपत्र में इनके अन्तिम रूप से प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कम्पनी सचिव विनियम 1982 में —

- (i) विनियम 55 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“55ग पश्च अर्हता सदस्यता पाठ्यक्रम

(55 (ग) विनियम 55ख में निर्धारित पश्चअर्हता सदस्यता पाठ्यक्रम विनियम 55घ से 55द तक अधिशासित होगा।”

- (ii) 55घ से 55द तक के विनियमों में जहां कहीं भी “पूँजीगत बाजार तथा वित्तीय सेवाएं” शब्द आते हैं, उनके स्थान पर ‘पश्च—अर्हता सदस्यता’ शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) 55घ विनियम के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करना

“55घ पश्च अर्हता पाठ्यक्रम की योजना तथा विषय इस प्रकार होंगे :

पाठ्यक्रम ‘क’ : पूँजीगत बाजार और वित्तीय सेवा पाठ्यक्रम

1. पूँजीगत बाजार और वित्तीय सेवा पाठ्यक्रम में निम्नलिखित दो भाग होंगे, अर्थात्

- (क) पाठ्यक्रम के भाग I में पहला ग्रुप 200 अंकों का होगा और दूसरा ग्रुप 300 अंकों का होगा; और
- (ख) पाठ्यक्रम के भाग II में शोध प्रबंध या परियोजना रिपोर्ट 150 अंकों की होगी तथा साक्षात्कार के लिए 50 अंक होंगे।

2. भाग I परीक्षा में परीक्षार्थी को पांच विषयों की परीक्षा देनी होगी, जिसमें दो ग्रुप होंगे और प्रत्येक में निम्नलिखित प्रश्नपत्र होंगे, अर्थात्

ग्रुप I : प्रश्न पत्र I : वित्तीय प्रबंधन — संकल्पना, मुद्दे और पद्धतियां।

प्रश्न पत्र II : वित्तीय सेवाएं, वित्तीय बाजार तथा वित्तीय उत्पाद।

ग्रुप II : प्रश्न पत्र III : प्रतिभूति मूल्यांकन और निवेश प्रबंधन।

प्रश्न पत्र IV : पोर्टफोलियो प्रबंधन तथा म्युच्युअल फंड।

प्रश्न पत्र V : अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन—संकल्पना, पूँजीगत बाजार और इस्ट्रुमेंट्स (लिखत)

3. पूंजीगत बाजार तथा वित्तीय सेवा पाठ्यक्रम के भाग I के पाठ्य-विवरण को अनुसूची घ में विनिर्दिष्ट किया गया है।

4. जो परीक्षार्थी पूंजीगत बाजार तथा वित्तीय सेवा पाठ्यक्रम में सफल होंगे, इंस्टीट्यूट उन्हें उपयुक्त रूप में डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करेगा और वे विवरणात्मक अक्षर तथा कोष्ठक में "डी.सी.एम.एफ.एस. (आई.सी.एस.आई.)" लिखने के हकदार होंगे जो इस बात का संकेत होगा कि परीक्षार्थी को इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया ने "पूंजीगत बाजार तथा वित्तीय सेवाओं (डी.सी.एम.एफ.एस.)" का डिप्लोमा प्रदान किया गया है।

पाठ्यक्रम ख: कार्पोरेट गवर्नेंस पाठ्यक्रम

1. कार्पोरेट गवर्नेंस पाठ्यक्रम में दो भाग होंगे, अर्थात्

(क) पाठ्यक्रम भाग I में पहला गुप 300 अंकों और दूसरा गुप 200 अंकों का होगा; और

(ख) पाठ्यक्रम के भाग II में शोध प्रबंध या परियोजना रिपोर्ट 150 अंकों की होगी तथा साक्षात्कार के लिए 50 अंक होंगे।

2. भाग I के परीक्षार्थियों की परीक्षा दो गुपों में पांच विषयों में होगी, जिसमें प्रत्येक में निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे, अर्थात्

गुप I प्रश्न पत्र I: कार्पोरेट गवर्नेंस का संकल्पनात्मक ढांचा

प्रश्न पत्र II: कार्पोरेट तथा बोर्ड प्रबंधन

प्रश्न पत्र III: कार्पोरेट गवर्नेंस का विधि ढांचा

गुप II प्रश्न पत्र IV: व्यावसायिकों की बोर्ड समिति तथा भूमिका

प्रश्न पत्र V: कार्पोरेट गवर्नेंस – संहिता तथा पद्धतियां

3. कार्पोरेट गवर्नेंस पाठ्यक्रम के भाग I का पाठ्य विवरण अनुसूची 'ड.' के अनुसार विनिर्दिष्ट रहेगा।

4. जो परीक्षार्थी कार्पोरेट गवर्नेंस पाठ्यक्रम में सफल होंगे, इंस्टीट्यूट उन्हें उपयुक्त रूप में डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करेगा और वे विवरणात्मक अक्षर और कोष्ठक में "डीसीजी (आई.सी.एस.आई.) लिखने के हकदार होंगे जो इस बात का संकेत होगा कि परीक्षार्थी को इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया ने "कार्पोरेट गवर्नेंस में पंच सदस्यता डिप्लोमा" प्रदान किया है।

(iv) अनुसूची घ में कोष्ठक के लिए, शब्दों और अंकों में

“विनियम 55 ग (3)” के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,
अर्थात् : — “देखिए विनियम 55 ध पाठ्यक्रम ए(3)”

(v) ‘अनुसूची घ’ के बाद निम्नलिखित अनुसूची अन्तर्विष्ट की जाएगी —

“अनुसूची ड”

[(देखिए विनियम 55 ध पाठ्यक्रम बी (3)]

कार्पोरेट गवर्नेंस में पश्च सदस्यता डिप्लोमा के भाग I का पाठ्य-विवरण

समग्र उद्देश्य और कार्यक्रम:

परीक्षार्थी को अपने वास्तविक जीवन में कार्पोरेट गवर्नेंस के बारे में अच्छी तरह से इसके सिद्धांतों तथा पद्धतियों को समझाने, विश्लेषण करने और लागू करने के लिए विशेष रूप से ज्ञान प्रदान करना है।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य सदस्यों को कार्पोरेट गवर्नेंस के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित कुशाग्र बुद्धि, सूक्ष्म दृष्टि और सम्पूर्ण जानकारी प्रदान कराना है। नीचे दिया गया पाठ्य-विवरण केवल एक दिशानिर्देश है और इसका अर्थ यह नहीं है कि परीक्षार्थी सूचीबद्ध क्षेत्रों तक ही सीमित रहे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे कार्पोरेट गवर्नेंस में उभरती संकल्पनाओं, नई घटनाओं, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों की भी सम्पूर्ण जानकारी रखें। परीक्षार्थियों से यह भी आशा की जाती है कि वे विश्व की नवीन प्रवृत्तियों और घटनाओं की भी जानकारी रखें ताकि कार्पोरेट गवर्नेंस का पूरा ढांचा समन्वित रूप से उनके सामने बना रहे, जिसमें कम्पनियों को अपना काम काज करना होता है। इस पाठ्यश्रव्या में भारत में जिस प्रकार का विधिगत एवं नियामक ढांचा बना हुआ है, उसके मुकाबले में कार्पोरेट गवर्नेंस तथा प्रक्रियात्मक, सचिवीय और प्रलेखन संबंधी पहलुओं की भी जानकारी होना आवश्यक है। परीक्षार्थियों को कार्पोरेट गवर्नेंस तथा निर्णय लेने के विषय में भी उनकी तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक रूप से भी पूरी तरह प्रवीण होना चाहिए। परीक्षार्थियों से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे अपने व्यावहारिक कार्य वाले क्षेत्रों के बारे में शोध प्रबंध अथवा परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करें और उनका यह शोध प्रबंध या परियोजना रिपोर्ट व्यावहारिक पहलुओं से जुड़ा होना चाहिए।

प्रत्येक प्रश्न पत्र तीन घण्टों का होगा और इसके 100 अंक होंगे। प्रश्न पत्रों का माध्यम अंग्रेजी होगा।

परन्तु परिषद् किसी खास प्रश्न पत्र में हिन्दी को भी माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकती है।

कार्पोरेट गवर्नेंस में पश्च सदस्यता डिप्लोमा का पाठ्य-विवरण

ग्रुप I – प्रश्न पत्र (I, II और III)

प्रश्न पत्र I

कार्पोरेट गवर्नेंस का संकल्पनात्मक ढांचा

उद्देश्य और कार्यक्षेत्र : कार्पोरेट गवर्नेंस का विकास तथा घटनाओं का गहन अध्ययन प्रदान करना।

विस्तृत विषय सूची

संगठन का अर्थशास्त्र एवं ज्ञान, कार्पोरेशन के सिद्धांत जिनका कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों पर प्रभाव पड़ता है।

कार्पोरेट गवर्नेंस का विकास – प्राचीन और आधुनिक संकल्पना

कार्पोरेट गवर्नेंस की संकल्पना, कार्य प्रदर्शन से प्राप्त मूल्य-वर्धन

कार्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत

कार्पोरेट गवर्नेंस के हितकारी; शेयरहोल्डरों की सक्रियता और संस्थागत निवेशकों की बदलती भूमिकाएं

कारोबारी नैतिकता बनाम कार्पोरेट गवर्नेंस

विभिन्न संगठनों में कार्पोरेट गवर्नेंस

कम्पनी के सामाजिक दायित्व और अच्छी कार्पोरेट नागरिकता

सूचना प्रौद्योगिकी और नॉन-स्टाप मीडिया कवरेज का प्रभाव जिससे कम्पनी सूचना पर अनियंत्रित पहुंच बनती है और प्राइवेट अधिकारों का उल्लंघन होता है।

शेयरहोल्डरों की सम्मति बनाम स्टेकहोल्डरों की गवर्नेंस सम्बन्धी संकल्पना।

प्रश्न पत्र II

कार्पोरेट और बोर्ड प्रबंधन

उद्देश्य और कार्यक्षेत्र : कार्पोरेट क्षेत्र को अधिशासित करने के बारे में संकल्पना, मुद्दे और पद्धतियों पर गहरी पैठ बनाना।

विस्तृत विषय सूची

कार्पोरेट कारोबार स्वामित्व ढांचा,

निदेशक मंडल — भूमिका, संयोजन, प्रणाली तथा प्रक्रियाएं

न्यासीय सम्बन्ध।

निदेशकों के प्रकार — प्रमोटर्स/नामिती/शेयरहोल्डर/निदेशकों के स्वतंत्र अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व, निदेशकों और एकजीक्यूटिव की भूमिका — नेतृत्व का उत्तरदायित्व, निदेशकों तथा एकजीक्यूटिवों के बीच सद्भाव

निदेशकों का प्रशिक्षण — आवश्यकता, उद्देश्य, तौर-तरीका

निदेशकों का कार्यक्षेत्र और उत्तरदायित्व तथा सक्षमताएं

एकजीक्यूटिव प्रबंधन प्रक्रिया, एकजीक्यूटिवों का पारिश्रमिक

बोर्ड की कामकाजी समितियां

शेयरहोल्डरों और अन्य स्टेकहोल्डरों के अधिकार तथा संबंध

निवेशकों की सर्विसिंग तथा निवेशक संरक्षण उपाए

अच्छी सचिवीय पद्धतियां और कार्पोरेट डिस्कलोजर के मानक

संगठनात्मक व्यवहार के मॉडल और प्रबंधकीय कार्य के प्रकार

संगठनात्मक संस्कृति तथा नियंत्रण

संगठनात्मक योजना, विकास और परिवर्तन

बाजार, हाईरार्की और नेटवर्क

स्ट्रेटेजी का अर्थशास्त्र, स्ट्रेटेजिक प्रबंधन, स्ट्रेटेजिक प्रबंधन के कार्य पर विहंगम दृष्टि

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सिद्धांत, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार और अन्तर्राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन

कर्मचारियों तथा ग्राहकों को अपनी तरफ करके चोट पहुंचाना

कार्पोरेशन और उसके कर्मचारी

ग्राहक सम्पदा प्रबंधन

उल्लेखनीय कार्पोरेट जोखिमों को मान्यता तथा उनका प्रबंधन; हैज फंड (दि वर्क—लाइफ बेलेंस तथा कार्पोरेट गवर्नेंस)

प्रबंधन लेखांकन तथा लेखा परीक्षा के सिद्धांत

कार्पोरेट योजना — अल्पकालिक तथा दीर्घकालीन

डिसास्टर मैनेजमेंट तथा नियंत्रण

प्रश्न पत्र III

कार्पोरेट गवर्नेंस का विधिगत तथा नियामक ढांचा

उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र : भारत तथा विदेशों में कार्पोरेट गवर्नेंस के बारे में विधिगत तथा नियामक ढांचे पर विशेष ज्ञान प्रदान करना।

विस्तृत विषय सूची

कार्पोरेट गवर्नेंस के विधि—निर्माण की आवश्यकता

कम्पनी विधेयक 1956 में कार्पोरेट गवर्नेंस के विधायी प्रावधान, प्रतिभूति (संविदा) विनियमावली विधेयक, 1956 (एस.सी.आर.ए.), डिपॉजिटरी एक्ट 1996, सेबी (भारत का प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड) विनियम एक्ट, 1992, सूचीबद्ध समझौता, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 तथा अन्य कार्पोरेट विधियां

निवेशकों के संरक्षण के लिए विधिगत प्रावधान

यू.एस., यू.के. तथा अन्य विकसित देशों के साथ साथ कामनवेल्थ एसोसिएशन फार कार्पोरेट गवर्नेंस (सी.ए.सी.जी.) सहित कार्पोरेट गवर्नेंस का विधायी ढांचा, आर्गेनाइजेशन फार इकानामिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (आई.सी.डी.) आदि

सूचीबद्ध आवश्यकताएं — भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

मेनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम (एम.आई.एस.) और कार्पोरेट डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स जिसमें लेखांकन मानक तथा सचिवीय मानक भी शामिल होंगे।

सांविधिक मानक तथा प्रक्रियाएं — राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय

सेबी इलेक्ट्रानिक डाटा इन्फार्मेशन फाइलिंग एंड रिट्रिवल सिस्टम (ई.डी.आई.एफ.ए.आर.)

ग्रुप II — प्रश्न पत्र IV और V

उद्देश्य और कार्यक्षेत्र: बोर्ड समितियों के कामकाज के बारे में विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त कराना।

विस्तृत विषय सूची

बोर्ड समितियां — लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति, शेयरहोल्डरों की शिकायत समिति, अन्य समितियां

समिति प्रबंधन की आवश्यकता, कामकाज और लाभ

बोर्ड समितियों का संविधान तथा कार्यक्षेत्र

बोर्ड समितियों का चार्टर

विचारणीय विषय तथा लेखांकन और कार्यप्रदर्शन का मूल्यांकन

समिति की बैठकों में उपस्थिति तथा भागीदारी

बोर्ड समितियों के सदस्यों की स्वतंत्रता

वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना; वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की सत्यनिष्ठा

बोर्ड समितियों में व्यावसायिकों की भूमिका

कार्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन में कम्पनी सचिवों की भूमिका

प्रश्न पत्र V — कार्पोरेट गवर्नेंस-संहिता तथा पद्धतियां

उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र : विश्व की प्रवृत्तियों और घटनाओं के बारे में सम्पूर्ण ज्ञान कराना ताकि कार्पोरेट गवर्नेंस के सम्पूर्ण ढांचे को समन्वित रूप में देखा जा सके।

विस्तृत विषय सूची

प्रमुख विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट — भारत (नरेश चन्द्र रिपोर्ट सहित) तथा विदेशों की रिपोर्टें

कार्पोरेट गवर्नेंस की संहिता का अध्ययन

संयुक्त उद्यम — राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय

कार्पोरेट कारोबार स्वामित्व ढांचे के बारे में केस अध्ययन, मूल क्षमता बनाम विविध कारोबार, ट्रांसनेशनल कार्पोरेशन की कार्यप्रणाली, सरकारी बनाम निजी क्षेत्र—राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय

कार्पोरेट गवर्नेंस के बारे में केस अध्ययन — भारत तथा विदेशी परिप्रेक्ष्य में

कार्पोरेट गवर्नेंस की उत्कृष्ट पद्धतियां

कार्पोरेट गवर्नेंस के माध्यम से मूल्य-वर्धन

कार्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग (फर्म डिस्कलोजर के संदर्भ में रेटिंग सम्बन्धी तंत्र-व्यवस्था)

एन. के. जैन, सचिव

[विज्ञापन-III/IV/असाधारण/121/2006]

टिप्पणी :— भारत के राजपत्र में मुख्य नियमावली के प्रकाशन के लिए देखिए अधिसूचना आई.सी.एस.आई. सं.710/2(1) दिनांक 16 सितम्बर 1982 तथा बाद में हुए संशोधनों के लिए निम्नलिखित अधिसूचनाएं देखिए :

- | | | |
|-------|--|---------------------------------|
| i) | अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई. / 710 / 2 / एम(1) | दिनांक 30.03.1984 |
| ii) | अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई. / 710 / 2 / एम(1) | दिनांक 03.05.1984 |
| iii) | अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई. / 710 / 2 / एम(1) | दिनांक 30.12.1985 |
| iv) | अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई. / 710 / 2 / एम(1) | दिनांक 09.09.1986 |
| v) | अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई. / 710 / 2 / एम(1) | दिनांक 23.02.1987 |
| vi) | अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई. / 710 / 2 / एम(1) | दिनांक 09.03.1987 |
| vii) | अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई. / 710 / 2 / एम(1) | दिनांक 22.08.1988 |
| viii) | अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई. / 710 / 2 / एम(1) | दिनांक 23.08.1988 |
| ix) | अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई. / 710 / 2 / एम(18) | दिनांक 22.08.1993 और 24.11.1993 |
| xi) | अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई. / 710 / 2 / एम(20) | दिनांक 28.11.1996 |
| xii) | अधिसूचना सं. आई.सी.एस.आई. / 710 / 2 / एम(26) | दिनांक 10.08.2001 |

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA**(Constituted under the Company Secretaries Act, 1980)****The Company Secretaries (Amendment) Regulations, 2006****(I. C. S. I. No. 2 of 2006)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th June, 2006

No. 710/1/(M)/1.—Whereas the draft regulations further to amend the Company Secretaries Regulations, 1982 were published as required by sub-section (3) of Section 39 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 2nd September, 2005 with the approval of the Central Government, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of forty-five days from the date on which the copies of said Gazette were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 5th September, 2005;

And whereas, no objections or suggestions were received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 read with sub-section (3) of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Council with the approval of the Central Government, makes the following regulations further to amend the Company Secretaries Regulations, 1982, namely:-

1. (1) These regulations may be called The Company Secretaries (Second Amendment) Regulations, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In the Company Secretaries Regulations, 1982 -

(i) for regulation 55C, the following regulation shall be substituted, namely: -

“55C Post Membership Qualification Courses

55C. The Post Qualification Courses as prescribed under regulation 55B shall be governed by regulations 55D to 55R.”

(ii) in regulations 55D to 55R for the words “Capital Markets and Financial Services” wherever they occur, the words “Post Membership Qualification” shall be substituted;

- (iii) for regulation 55S, the following regulations shall be substituted, namely:-

Grant of Diploma Certificate

55S The scheme and the subjects of the Post Qualification Courses shall be as follows: -

Course A: Capital Markets and Financial Services Course

- (1) The Capital Markets and Financial Services Course shall comprise of following two parts, namely -

- (a) Part I of the course shall consist of Group I of 200 marks and Group II of 300 marks; and
- (b) Part II of the course shall consist of dissertation or project report of 150 marks and interview of 50 marks.

- (2) The candidates for Part I examination shall be examined in five subjects comprised in two Groups each consisting of the following papers, namely -

Group I - Paper I : Financial Management - Concepts, Issues and Practices.

Paper II : Financial Services, Financial Markets and Financial Products.

Group II - Paper III: Security Evaluation and Investment Management.

Paper IV : Portfolio Management and Mutual Funds.

Paper V : International Financial Management-Concepts, Capital Markets and Instruments.

- (3) The syllabus for Part I of Capital Markets and Financial Services Course shall be as specified in Schedule D.

- (4) A candidate successfully completing the Capital Markets and Financial Services Course shall be awarded a Diploma Certificate to that effect in the appropriate form by the Institute and shall be entitled to use the descriptive letters and bracket "DCMFS (ICSI)" to indicate that he has been awarded "Post Membership Diploma in Capital Markets and Financial Services" (DCMFS) by the Institute of Company Secretaries of India.

Course B: Corporate Governance Course

- (1) The Corporate Governance Course shall comprise of following two parts, namely-

- (a) Part I of the course shall consist of Group I of 300 marks and Group II of 200 marks; and
- (b) Part II of the course shall consist of dissertation or project report of 150 marks and interview of 50 marks.
- (2) The candidates for Part I examination shall be examined in five subjects comprised in two Groups each consisting of the following papers, namely -
- Group I Paper I : Conceptual Framework of Corporate Governance
 Paper II : Corporate and Board Management
 Paper III : Legal Framework of Corporate Governance
- Group II Paper IV : Board Committees and Role of Professionals
 Paper V : Corporate Governance — Codes and Practices
- (3) The syllabus for the Part I of Corporate Governance Course shall be as specified in Schedule E.
- (4) A candidate successfully completing the Corporate Governance Course shall be awarded a Diploma Certificate to that effect in the appropriate form by the Institute and shall be entitled to use the descriptive letters and bracket "DCG (ICSI)" to indicate that he has been awarded "Post Membership Diploma in Corporate Governance" by the Institute of Company Secretaries of India;

- (iv) in Schedule D, for the brackets, words and figures
 "[Regulation 55C (3)]", the following shall be substituted, namely:-
 "[See regulation 55S course A (3)]";
- (v) after Schedule D, the following Schedule shall be inserted,
 namely: -

Schedule E
[See regulation 55S course B (3)]

Syllabus for Part I Post Membership Diploma in Corporate Governance

Overall objective and scope :

To provide expert knowledge to understand, analyse and apply the principles and practices of Good Corporate Governance in real life situations.

The prime objective of this Diploma Course is to enable the members to gain acumen, insight and thorough knowledge relating to the various aspects of corporate governance. The syllabus given below is merely a guideline and need not necessarily be construed to be restricted to the areas listed therein. The candidates are expected to have thorough knowledge of the emerging concepts in corporate governance, new developments, issues at national and international levels. The candidates are further expected to have thorough knowledge of the global trends and developments so as to have an integrated view of the entire framework for corporate governance within which the companies operate. Knowledge of the legal and regulatory framework in India vis-à-vis corporate governance as well as procedural, secretarial and documentation aspects will also form part of this curriculum. The candidates should be fully equipped with the technical and analytical skills in corporate governance and decision making. The candidates will also be expected to submit dissertation or project report in the areas in which they have practical exposure and that the dissertation or project report should be on practical aspects.

Each paper will be of three hours duration and will carry 100 marks. The medium of writing the examination will be English:

Provided that it shall be competent to the Council to permit the use of Hindi as a medium of writing any particular paper.

SYLLABUS FOR POST MEMBERSHIP DIPLOMA IN CORPORATE GOVERNANCE

GROUP I – PAPERS (I, II and III)

PAPER I

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF CORPORATE GOVERNANCE

Objective and scope: To provide an in-depth study of the Evolution and Development of Corporate Governance.

Detailed Contents:

Economics of Organization and Information, Theories of the Corporation that have a shaping influence upon Corporate Governance Practices

Evolution of Corporate Governance – Ancient and Modern Concept

Concept of Corporate Governance, Generation of Value from Performance

Principles of Corporate Governance

Beneficiaries of Corporate Governance; Shareholder Activism and changing role of Institutional Investors

Business Ethics vis-à-vis Corporate Governance

Corporate Governance in various organizations

Corporate Social Responsibilities and good corporate citizenship

Impact of Information Technology and Non-stop Media Coverage giving unbridled access to company information and violating privacy rights
Understanding of the shareholder Vs. stakeholder concept of governance

PAPER II

CORPORATE AND BOARD MANAGEMENT

Objective and scope: To provide a detailed insight into the concept, issues and practices that governs the corporate sector.

Detailed Contents:

Corporate Business Ownership Structure
Board of Directors – Role, Composition, Systems and Procedures
Fiduciary relationship
Types of Directors- Promoter/Nominee/Shareholder/Independent
Rights, Duties and Responsibilities of Directors; Role of Directors and Executives –
Responsibility for Leadership, Harmony between Directors and Executives
Training of Directors- need, objective, methodology
Scope and Responsibilities and competencies for directors
Executive Management Process, Executive Remuneration
Functional Committees of Board
Rights and Relationship of Shareholders and Other Stakeholders
Investor servicing and investor protection measures
Good Secretarial practices and Standards for corporate disclosure
Models of organizational behaviour and nature of managerial work
Organisational cultures and controls
Organisational Planning, Development and change
Markets, Hierarchies and Networks
Economics of Strategy; Strategic Management; Overview of Task of Strategic Management
Theory of Multi-nationals, International Marketing and International Resource Management
Attacks through hijacking of employees and customers
Corporation and its Employees
Customer Asset Management
Recognition and Management of significant corporate risks; hedge funds (The work-life balance and corporate governance)
Principles of Management Accounting and Audit
Corporate Planning- Short term and Long term
Disaster Management and Control

PAPER III**LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK OF CORPORATE GOVERNANCE**

Objective and Scope: To provide expert knowledge of the legal and regulatory framework in respect of corporate governance in India and abroad.

Detailed Contents:

Need for Legislation of Corporate Governance

Legislative Provisions of Corporate Governance in the Companies Act, 1956, the Securities Contracts (Regulations) Act, 1956 (SCRA), the Depositories Act, 1996, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Listing Agreement, the Banking Regulation Act, 1949 and Other Corporate Laws

Legal Provisions relating to Investor Protection

Legislative Framework of Corporate Governance in United States, United Kingdom and other developed countries including Common Wealth Association for Corporate Governance (CACC), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), etc.

Listing Requirements: Indian and International perspective

Management Information System (MIS) and Corporate Disclosure Requirements covering Accounting Standards and Secretarial Standards also.

Statutory standards and procedures – National and international

Securities and Exchange Board of India's (SEBI) Electronic Data Information Filing and Retrieval System (EDIFAR)

GROUP II – PAPERS (IV AND V)**PAPER IV - BOARD COMMITTEES AND ROLE OF PROFESSIONALS**

Objective and Scope : To provide expert knowledge on the functioning of Board Committees.

Detailed Contents:

Board Committees - Audit Committee, Remuneration Committee, Shareholders' Grievance Committee, Other Committees.

Need, Functions and Advantages of Committee Management

Constitution and Scope of Board Committees

Board Committees' Charter

Terms of Reference and Accountability and Performance Appraisals

Attendance and participation in committee meetings

Independence of Members of Board Committees

Disclosures in Annual Report; Integrity of Financial Reporting Systems

Role of Professionals in Board Committees

Role of Company Secretaries in compliance of Corporate Governance

PAPER V – CORPORATE GOVERNANCE – CODES AND PRACTICES

Objective and Scope : To provide thorough knowledge of the global trends and developments so as to have an integrated view of the entire framework for corporate governance.

Detailed Contents :

Major Expert Committees' Reports- India (including Naresh Chandra Report) and Abroad

Study of Codes of Corporate Governance

Joint Ventures-National and International

Case Studies on Corporate business ownership structure, Core competency vis-à-vis diversified business, Working of Transnational Corporations, Public Vs Private Sector – National and International

Case Studies on Corporate Governance - Indian and overseas perspective

Best Practices of Corporate Governance

Value Creation through Corporate Governance

Corporate Governance Ratings (Rating mechanism in terms of firm disclosures).

N. K. JAIN, Secy.

[ADVT. III/IV/Exty/121/2006]

Note:— The principal Regulations were published in the Gazette of India vide notification ICSI No.710/2 (1) dated 16th September, 1982 and subsequently amended vide :-

- | | | |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------|
| i) | Notification No. ICSI/710/2/M (1) | dated 30.03.1984 |
| ii) | Notification No. ICSI/710/2/M (1) | dated 03.05.1984 |
| iii) | Notification No. ICSI/710/2/M (1) | dated 30.12.1985 |
| iv) | Notification No. ICSI/710/2/M (1) | dated 09.09.1986 |
| v) | Notification No. ICSI/710/2/M (1) | dated 23.02.1987 |
| vi) | Notification No. ICSI/710/2/M (1) | dated 09.03.1987 |
| vii) | Notification No. ICSI/710/2/M (1) | dated 22.08.1988 |
| viii) | Notification No. ICSI/710/2/M (1) | dated 23.08.1988 |
| ix) | Notification No. ICSI/710/2/M(18) | dated 20.08.1993 and 24.11.1993 |
| x) | Notification No. ICSI/710/2/M(20) | dated 28.11.1996 |
| xi) | Notification No. ICSI/710/2/M(26) | dated 10.08.2001 |